*International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*
*ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714*
*www.ijhssi.org ||Volume 11 Issue 8|| August 2022 || PP. 93-95*

# वर्तमान शैक्षिक व्यवस्था में गुणवत्ता की समस्या

डा.सुप्रिया पांडेय

*असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग*

*आचार्य नरेंद्र देव नगर निगम महिला महाविद्यालय, हर्ष नगर ,कानपुर*

***सोध सारांशः*** *शिक्षा व्यवस्था किसी भी समाज के सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक है। यह वह माध्यम है ,जो बालकों का समाजीकरण कर उनको समाज के आदर्श मूल्य एवं संस्कारों से अवगत कराता है। इतिहास गवाह रहा है की जिन समाजों ने अपने वहां शिक्षा को महत्त्व प्रदान किया, संस्थागत रूप दिया एवम परिवर्तन और आधुनिकता को, शिक्षा व्यवस्था में समाहित करने के लिए सदैव तत्पर रहाए वहां का समाज सुखी ,समृद्ध और गौरवशाली अतीत के साथ दीर्घजीवी रहा। नहीं तो इस धरा पर बहुत सारे समूह आए और अपने अस्तित्व की रक्षा न कर पाए। शिक्षा वह कारक है जो सर्वप्रथम मानव को पशु जगत से पृथक करती है। मनुष्य को अपने प्रकृतिक गुणों पर नियंत्रण सीखने में मदद करती है। जिससे समाज में व्यवस्था कायम रहे। समाज के लिए आवश्यक संसाधनों को विकसित, परिवर्धित करने हेतु शिक्षा ही नए–नए ज्ञान, विज्ञान और यंत्रों का विकास करने में मदद करती है।*

***कुंजी शब्द–*** *सामाजिक परिवर्तन, सामाजिकरण, आदर्श, मूल्य, नौकरशाही, सामाजिक अंकेक्षण*

वर्तमान परिवेश में हम शिक्षा को 3 भागों मैं संस्थागत रूप से बटा हुआ पाते हैं। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। जहां प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाया गया है, शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है। वही माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को योग्य और उचित व्यक्तियों के लिए सुलभ किया गया है। इन तमाम उपायों तथा योजनाओं द्वारा प्रयास रहा है की निरक्षरता कम हो, साक्षरता का विकास हो, देश में योग्य नागरिक तथा कुशल नेतृत्व का विकास हो। शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षर बनाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि आम जनमानस को इस योग्य बनाने के लिए आवश्यक गुणों से युक्त करने का भी रहा है कि वह जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं को जुटाने में समर्थ हो सके, सहज हो सके साथ साथ सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकारने एवं उनके प्रतिउत्तर के प्रति सजग होना और उनके साथ तादात्म्य स्थापित करने में ,अपने को समर्थ बना सके। कहना ना होगा की हमारी शिक्षा व्यवस्था ने देश को निरक्षरता के घने अंधकार से, बाहर निकाल कर के साक्षरता की महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लक्ष्य को प्राप्त किया है। तदैव वह अन्य मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा है। यह लक्ष्य उतने ही महत्वपूर्ण थे जितना की साक्षरता दर बढ़ाना। जीवन निर्वाह करने में समर्थ, आत्मनिर्भर ,स्वविवेकी, समाजिकरण से युक्त बालक तथा अच्छे नागरिक पैदा करना भी किसी भी शिक्षा व्यवस्था के अनिवार्य लक्ष्य हैं। हमे सोचना होगा कि कौन से कारण हैं जो, शिक्षा व्यवस्था के आकार को तो बढ़ा दिए परंतु उन पर गुणवत्ता नियंत्रण स्थापित करने में विफल रहे ।

जहां तक प्राथमिक शिक्षा की बात है, बहुसंख्य मात्रा में प्राथमिक पाठशालाओं का निर्माण हुआ है । पहले से अधिक अच्छी डिग्री प्राप्त शिक्षकों का पदार्पण हुआ है। इस क्षेत्र में तथापि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कहना कि सभी सरकारी कर्मचारियों के बच्चे प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ें, तभी उनकी दशा सुधार हो सकता है यह अपने आप में प्राथमिक पाठशालाओं के गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। आखिर कौन से ऐसे कारक हैं जो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चशिक्षाओं में पठन–पाठन के माहौल को निम्न बना रहे हैं । हमें उन पर गौर करना होगा। प्रथम कारक बच्चे हैं , बच्चे ही वे मुख्य कारक है जिनकी हेतु यह सारी कवायद की जा रही है। अगर बच्चे ही उपस्थित ना हो विद्यालयों में तो, सारा शैक्षणिक तंत्र ना केवल अपने प्रभाव में बेकार घोषित हो जाएगा अपितु उसका होना भी निरर्थक है। तो बच्चे कैसे संस्थानों में आएं, कैसे उनका प्रवेश हो , प्रवेश प्रक्रिया क्या हो, उसमें भेदभाव कैसे किया जाए और कैसे भेदभाव से बचा जाए, इस पर अवश्य ही गौर किया जाना चाहिए। कोई तुक नहीं है की अयोग्य को उच्च शिक्षा हेतु आगे बढ़ाया जाए और योग्य को विभेदकारी नीतियों के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने से रोक दिया जाए। तथापि हमें यह भी देखना होगा की प्राथमिक शिक्षा में तो तो बच्चे जीरो से ही प्रारंभ करते हैं। तो वहां कौन सी समस्या है । वहां विभेदकारी व्यवस्था मुख्य समस्या नहीं है। वहां समस्या है बच्चों का स्कूल में न आना, नबने रहना । शैक्षिक माहौल का दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो है वह है योग्य शिक्षकों का न होना होना। वैसे आज कल का शिक्षक तमाम प्रशिक्षण संबंधी योग्यताओं से युक्त है। अच्छे वेतनमान पर नियुक्त है। तथापि वह उचित शैक्षणिक माहौल बनाने में कई कारणों से य खासकर सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में असमर्थ रहा है। इसमें सबसे मुख्य बात है की प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण स्थानीय ना हो के जिला मुख्यालयों से निर्देशित होता है। जिससे अभिभावकों और संबंधित जनमानस का पाठशालाओं से रूचि जाती रहती है । सामाजिक दबाव के अभाव में केवल नौकरशाही रूपी नियंत्रण से यह व्यवस्था यजो दूर दूर ग्रामीण अंचलों तक फैली हुई है, कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। किसी भी सामाजिक संस्था की उपादेयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि ,उसकी सामाजिक अंकेक्षण की भी व्यवस्था हो। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की सोशल आडिट की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हमारा समाज

इतना साक्षर हो गया है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इन सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का सामाजिक नियंत्रण कर सकें । विद्यालयों में पठन–पाठन तथा शिक्षकों की उपस्थिति अनुपस्थिति हेतु ,अधिकार एवं दायित्व वहां के स्थानीय लोगों में ही निहित होना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त हमें इस पर भी ध्यान देना होगा कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षा का केंद्र है नकी समाज कल्याण का। अगर हम इनको शिक्षा का केंद्र ही रहने दे, तो ही इन की गुणवत्ता में सुधार हो पाएगा । आजकल देखा जा रहा है कि सरकार समाज कल्याण के कार्यक्रमों को सरकारी स्कूलों को केंद्र बना कर लागू कर रही है । ध्यान रखिए समाज कल्याण विभाग की विफलता को सरकारी प्राथमिक स्कूल नहीं ढो सकते । हमें समाज कल्याण के कार्यक्रमों को चालू रखने के लिए और कोई सेंटर चुनने होंगे। कृपया शिक्षा के केंद्र को शैक्षिक दृष्टिकोण से ही चलने दें। इस पर गरीबी निवारण योजनाओं, भुखमरी निवारण योजनाओं, कपड़ा वितरण योजनाओं या अन्य किसी भी तरह की कल्याणकारी योजनाओं का केंद्र ना बनाएं। यदि छात्र शिक्षा की भूख लिए पाठशाला में आएगा यतो निश्चित ही शिक्षा की पिपासा शांत करेगा और अगर छूधा की भूख लिए आएगाय तो केवल छूधा की भूख ही शांत कर पाएगा । अतः पेट की भूख शांत करने के लिए कोई और समानांतर एजेंसी कायम की जाए। पाठशालाओं को शिक्षा का केंद्र ही रहने दिया जाए । इसका तात्पर्य यह नहीं है की बच्चे भूखे रहे। उनको छात्रवृत्ति ना मिले ।उनको ड्रेस ना मिले। हां यह जरूर कहता हूं कि कृपया इन सब में स्कूल का कोई रोल ना हो। स्कूल का रोल केवल और केवल बच्चों के शैक्षिक और बौद्धिक विकास में ही हो । स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी तथा अधिकारी केवल इस बात की चिंता करें कि कैसे शिक्षा के स्तर का उन्नयन हो। और हमारे छात्र समुचित तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पा सके इसकी व्यवस्था कैसे हो।

आज बेसिक शिक्षा अधिकारीय जिला विद्यालय निरीक्षक या इसी तरह के कार्यालयों में कार्यरत अन्य लोगों काय अधिकांश समय शिक्षा व्यवस्था के संचालन पर नहीं बल्कि इन कल्याणकारी योजनाओं के समन्वय एवं संचालन पर खर्च होता है। तो सोचा ही जा सकता है कि शिक्षा की गुणवत्ता कहां से आए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें सोचना होगा कि विद्यालय शिक्षा का केंद्र है या गरीबी निवारण योजनाओं का। अगर आप इसको गरीबी निवारण योजनाओं का मुख्य केंद्र मानते हैं तो वहां अध्यापकों की नियुक्ति बंद करिएय और उनसे बचने वाले सभी धन राशियों को बच्चों में वितरित कर दीजिए। ऊंचे वेतन पर नियुक्त हमारे अध्यापकय ड्रेस वितरण छात्रवृत्ति वितरणय बाल गणनाय जनगणनाय भवन बनवाने का लेखा जोखा रखनाय भवनों का मरम्मत करानाय सूचनाएं लेकर समन्वय केंद्रों से लेकर य जिले तक दौड़ लगाना, इन सब कामों के लिए नहीं है । इसके लिए तो सामान्य सा अहर्ता प्राप्त कलर्क या सुपरवाइजर ही पर्याप्त है । फिर हम प्रशिक्षण धारी व्यक्तियों को इन कामों पर क्यों नियुक्त करें ? हमें दोनों तरफ तरफ से नुकसान हैं । एक तरफ तो शिक्षा व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ लादकर गुणवत्ता से समझौता कर रहे हैं । तो दूसरी ओर ऐसे लोगों द्वारा असंबद्ध कामों को करा कर उस व्यवस्था को भी चोट पहुंचा रहे ।अगर प्राथमिक सरकारी पाठशालाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का केंद्र बनाना है तो हमें उपरोक्त घटकों पर ध्यान देना ही होगा ।

माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की बात करें तो तमाम अच्छाइयों के बावजूद विगत एक दशक से यहां भी गिरावट प्रकट हुई है । इन सब के पीछे जहां प्राथमिक स्तर के गुणवत्ता रहित शिक्षा ने अपना योगदान दिया है वही शिक्षा के निजीकरण तथा व्यवसायिकरण ने , कोढ़ में खाज का काम किया है । बढ़ते स्ववित्तपोषित विद्यालयों ने, विद्यालय स्थापित करने के परंपरागत पुण्यार्थ उद्देश्यों को बदल डाला है। आज विद्यालय पुण्यार्थ उद्देश्य के लिए नहीं स्थापित किए जाते। आज इनकी स्थापना धन से होती है और धन के लिए होती है। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तो गौड विषय हो गया है। और धन के लिए प्रबंधन कुछ भी करने को तैयार है। बच्चों से पैसे वसूले जाते हैं और उनका प्रयोग परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था बनाने तथा नकल कराने में अधिकाधिक होता है। न की शिक्षा देने मे । मै यह नहीं कहता की शिक्षा के निजीकरण में शिक्षा को लाभ नहीं पहुंचा है । जहां विद्यालय महाविद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है, छात्रों को विकल्प मिला है, प्रतियोगिता बड़ी है, लेकिन इन सब के साथ साथय एक नई तरह की निर्लज्ज नकल प्रणाली ने, शिक्षा व्यवस्था में तेजी से कदम बढ़ा दिया है। और यह हमारे संस्थानों को दीमक के जैसे खाए जा रही है । अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने शिक्षा माफिया का जिक्र अपने जनसभा में किया था। समस्या यह नहीं है कि इससे हमारे नेतागण या अधिकारी परिचित नहीं हैं। समस्या यह है की इसे दूर कैसे किया जाए।

अगर महामहिम राष्ट्रपति अपने संबोधन में यह दुख प्रकट करते हैं की टॉप 100 में हमारा कोई भी विश्वविद्यालय अपना स्थान नहीं बना पाया है यतथा नए–नए आविष्कार और शोध में कमी आई है। तो हमें सोचना होगा की ऐसा क्यों है ? मुझे लगता है की पूरी शैक्षिक प्रणाली में मुख्य समस्या अब आकार की नहीं रही। पर्याप्त मात्रा में सरकारी अथवा निजी क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थानों की स्थापना हो गई है। अब मुख्य समस्या इनके नियंत्रणकारी संस्थानों की कुशलता बढ़ाने की है । यह संस्थान बरसों पुराने अपने कार्यविधिओं को ही अपनाए हुए है। जबकि उनके द्वारा नियंत्रित स्कूलों के आकार तथा प्रकार में व्यापक परिवर्तन हो चुके हैं। हमें ऐसे नियंत्रणकारी संस्थानों में भी व्यापक परिवर्तन लाना होगा । यह संस्थान हैं, परीक्षा लेने वाली संस्थाएं, अध्यापकों की उपस्थिति दर्ज करने वाली संस्थाएं, उनको वेतन देने वाली संस्थाएं, बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने वाली संस्थाएं। इन तीनों में तकनीक के प्रयोग की बहुत गुंजाइश है । शिक्षक तथा विद्यार्थी सही समय पर तथा नियमित तौर पर विद्यालय में उपस्थित हो इसके लिए ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग किया जा सकता है । इसी तरह से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करते हुए सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जा सकता है। इससे शिक्षकों की व्यर्थ की भागदौड़, मीटिंग से समय बचेगाय और वे भी बच्चों पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। नियंत्रक संस्थाओं मे अधिकतम तकनीक प्रयोग को अपनाना होगा। जिससे मानव हस्तक्षेप कम से कम हो सके और व्यवस्था सुदृढ़

हो सके। इसी तरह से परीक्षा प्रणाली में भी नकल व्यवस्था को रोकने के लिए अधिकाधिक ऑनलाइन सीसीटीवी कैमरों का उपयोग किया जाए। परीक्षा प्रपत्र बनाने से लेकर परीक्षा देने और कॉपियों के मूल्यांकन तकय प्रतिपल कैमरे की जद में हो। और इनका व्यापक निगरानी की जाए । जहां कहीं गड़बड़ी दिखे सिस्टम अपने आप ही उनको रोक पाए। ऐसा व्यवस्था कायम करना होगा। तभी हम नकल व्यवस्था पर रोक लगा पाएंगे और विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास कर पाएंगे।

उपरोक्त सुझाव के कुछ मुख्य बिंदु रहे हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाए तो निश्चित ही हम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए उत्तम शैक्षिक परिवेश देने में समर्थ हो सकेंगे। और अपने विद्यार्थियों, गुरुजनों और समाज को नैतिक और सामाजिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने में सफल हो पाएंगे। हमारी शिक्षा प्रणाली ने बहुत सारे दुरूह लक्ष्य प्राप्त किए हैं। हम अब भी सक्षम हैं की अपने परिवेश को सुधार सकें और कह सकें की उठो जागो और आगे बढ़ो । हमें जगाना होगा अपने सुषुप्तावस्था में पड़े शैक्षिक नियंत्रण तंत्र को, हमें जगाना होगा।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

1. डा. रमन बिहारी '' भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं '' राज प्रिंटर्स , मेरठ.
2. शुक्ला डा. सी. एस. '' उदयीमान भारतीय समाज में शिक्षक '', इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस , मेरठ
3. शर्मा रामनाथ व शर्मा राजेन्द्र कुमार,''शैक्षिक समाजशास्त्र 2006 ''
4. राय डा. कुमार विजय, मिश्रा डा. रमेश चन्द्र, '' भारत में शिक्षा के मुद्दे एवं चुनौतियां , ठाकुर पब्लिकेशन , लखनऊ
5. सिंह डा. के. बी. , '' शिक्षा के विविध आयाम ''
6. कुरुक्षेत्र
7. योजना